Dr. ... Dept. of Economics
Raja Singh College
Siwan
10.7.20

भारत में कृषि व्यवस्था के विभिन्न स्वरूप :-
DIFFERENT FORMS OF CULTIVATION IN INDIA

– कृषि तथा किसानों की आर्थिक स्थिति का जोतों के आकार से बड़ा ही घनिष्ठ सम्बन्ध है। किसी भी देश में कृषि का मूलभूत उद्देश्य उत्पादन में वृद्धि, किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार तथा इनके लिए सामाजिक न्याय की व्यवस्था करना होना चाहिए। उत्पादन में वृद्धि के फलस्वरूप यह भी आवश्यक है कि कृषि के उत्पादन का एक भाग बाज़ार में बिक्री के लिए ले जाया जाए, ताकि कारखानों में काम करनेवाले श्रमिकों के लिए भी कृषि-वस्तुएँ उचित कीमत पर उपलब्ध हो सकें। दूसरे शब्दों में, विक्रय-अधिशेष की मात्रा में वृद्धि हो। विकास के लिए उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि जितनी आवश्यक है उतनी ही विक्रय-अधिशेष (Marketable surplus) में वृद्धि भी आवश्यक है।

विश्व में आजकल कृषि-व्यवस्था के निम्नलिखित पाँच प्रमुख स्वरूप पाये जाते हैं-

1. व्यक्तिगत कृषि-व्यवस्था (Individual or Peasant farming)
2. पूँजीवादी कृषि-व्यवस्था (Capitalistic Farming)
3. राजकीय कृषि-व्यवस्था (State Farming)
4. सामूहिक कृषि-व्यवस्था (Collective Farming)
5. सहकारी कृषि-व्यवस्था (Co-operative Farming)

Scanned by CamScanner

1. व्यक्तिगत कृषि - व्यवस्था (Peasant Farming)

इस व्यवस्था में किसान अपनी भूमि या किराये की जमीन पर अपने साधनों से कृषि का कार्य करता है। भारत में इस प्रकार की कृषि - व्यवस्था ही अधिकर प्रचलित है। इसमें किसान बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप के स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य करता है। साधारण तौर पर कृषक भू-स्वामी वाली कृषि अथवा व्यक्तिगत खेती को ही कृषि का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप माना जाता है। कहा जाता है कि यह कृषि-प्रणाली इतनी अच्छी है कि इसके अन्तर्गत भूमि सामान्यतया सोना उगलती है।

2. पूँजीवादी कृषि-व्यवस्था (Capitalist Farming)

इस प्रकार की कृषि-व्यवस्था इंगलैंड तथा अमेरिका जैसी पूँजीवादी व्यवस्था वाले देशों में अधिक प्रचलित है। भारत में भी चाय, कहवा तथा रबर के बागानों में इसी प्रकार की कृषि - व्यवस्था पायी जाती है। दक्षिणी भारत में गन्ने की खेती में भी बड़े-बड़े फार्म पाये जाते हैं। इस व्यवस्था में भूमि पर ~~व्यक्तियों~~, सिण्डीकेटों अथवा संयुक्त पूँजी कम्पनियों का अधिकार रहता है तथा वे ही इसके प्रबन्धकर्ता भी होते हैं। इनमें उत्पादन के आधुनिक तरीके वाली उन्नत बीज, अच्छी खाद तथा बड़े-बड़े यंत्रों का उपयोग किया जाता है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत पूँजीपति भूमि पर ~~थोड़े ही व्यक्तियों का अधिकार हो जायेगा जिससे देश में भूमिहीन वर्ग की संख्या में~~ वैज्ञानिक ढंग से बड़े पैमाने पर कृषि का कार्य करते हैं। अतः इस प्रकार की व्यवस्था हितकर नहीं सिद्ध होगी क्योंकि इस व्यवस्था में भूमि पर थोड़े ही

Scanned by CamScanner

व्यक्तियों का अधिकार हो जाएगा जिससे देश में भूमिहीन वर्ग की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। साथ ही यन्त्रों के अधिकाधिक उपयोग से बेकारी बढ़ने का भी भय बना रहेगा। अतः आज की स्थिति में भारत के लिए यह व्यवस्था उपयुक्त नहीं होगी।

3. राजकीय कृषि-व्यवस्था (State Farming)

राजकीय अथवा सरकारी कृषि-प्रणाली की भी लगभग वही विशेषताएँ हैं जो बड़े आकार वाले पूँजवादी फार्मों की के सम्बन्ध में देखने को मिलती हैं। इसके अन्तर्गत भी कृषि की खाई बड़ी होती है तथा उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। साथ-ही, कृषि-साधनों का प्रयोग भी बड़ी मात्रा में किया जाता है लेकिन इसमें भूमि पर राज्य का स्वामित्व रहता है। अतएव सरकारी स्वामित्व के कारण इसकी कुछ विशेषताएँ हैं जो इसे पूँजवादी कृषि तथा अन्य बड़े पैमाने की की कृषि-प्रणाली से अलग करती हैं।

4. सामूहिक कृषि (Collective Farming)

यह कृषि-प्रणाली पुराने सोवियत रूस तथा चीन जैसे साम्यवादी देशों में प्रचलित है। इजरायल भी इस प्रकार की कृषि का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करता है। सामूहिक कृषि के अंतर्गत समाज की सम्पूर्ण भूमि को मिलाकर एक कर दिया जाता है और उसमें बड़े पैमाने पर कृषि की जाती है।

Scanned by CamScanner

भूमि पर से व्यक्तिगत स्वामित्व समाप्त कर दिया जाता है तथा सम्पूर्ण भूमि पर समाज का सामूहिक अधिकार हो जाता है। दो एक दृष्टियों से यह प्रणाली भी अच्छी भी है।

6. सहकारी कृषि - व्यवस्था
(Co-operative Farming)

यह सामूहिक कृषि तथा व्यक्तिगत कृषि के बीच एक समझौता है। डॉ० ओटो शिलर (Otto Schiller) के अनुसार, "सहकारी कृषि-व्यवस्था का वह रूप है जिसमें भूमि का प्रयोग संयुक्त रूप में किया जाता है।" (Co-operative farming is understood as a form of farm management in which the land is used jointly) इसी प्रकार 1959 में निजलिंगप्पा समिति ने अपने प्रतिवेदन में सहकारी कृषि की परिभाषा इस प्रकार से दी थी - "सहकारी कृषि - समिति कृषकों का एक ऐच्छिक संगठन है जिसमें मानव - शक्ति एवं भूमि जैसे साधन एकत्र किये जाते हैं जिससे उनका अच्छा प्रयोग हो सके। इसमें अधिकांश सदस्य कृषि में भाग लेते हैं जिससे उत्पादन, रोजगार तथा आय बढ़ती है। इस प्रकार की व्यवस्था में किसान आपस में मिलकर खेती का कार्य करते हैं। इसमें व्यक्ति का अपनी भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार ज्यों-का-त्यों बना रहता है, लेकिन खेती संयुक्त रूप से ही की जाती है।